

◦ सेवा:

- इसमें गोशालाओं में श्रम कार्य एवं नागरिक नकियों के कार्यालयों में 'मल्टीटास्क सेवाएँ', रिकॉर्ड कीपिंग आदि शामिल हैं। साथ ही वरिष्ठ संरक्षण से संबंधित कार्य भी शामिल हैं।
- विविध कार्य, जैसे कि सुरक्षा/बाड़ लगाना/चारदीवारी/नगरीय नकियों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा से संबंधित कार्य, शहरी नकिय की सीमा के भीतर पार्कग स्थलों का विकास व प्रबंधन, आवारा पशुओं को पकड़ना तथा उनका प्रबंधन करना आदि।

शहरी क्षेत्रों के लिये सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता:

- **अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता:** शहरी क्षेत्र देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अधिकांश देशों की तरह भारत के शहरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं।
 - भारतीय शहर आर्थिक उत्पादन में लगभग दो-तर्हिई का योगदान करते हैं, जनसंख्या के एक बढते हिस्से की मेज़बानी करते हैं और **भारतीय क्षेत्र वदिशी नविश (FDI)** के मुख्य प्राप्तकर्ता हैं। वे नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के प्रवर्तक भी हैं।
- **व्यवसायों के लिये आकर्षण का केंद्र:**
 - शहर आर्थिक गतिविधियों की व्यापक विविधता के लिये एक सामूहिक आकर्षण केंद्र की स्थिति भी रखते हैं।
 - अनुमापी और संकुलन लाभों (शैक्षिक सुविधाओं की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति आदि) के परिणामस्वरूप शहर व्यवसाय एवं लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं।
- **सामाजिक पूंजी का केंद्र:**
 - शहर सामाजिक पूंजी का केंद्र होते हैं। वे सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण समूहों के 'मलिन बटु' या भिन्न-भिन्न विचारों पर चर्चा का केंद्र होने की स्थिति भी रखते हैं।
- **शक्तिके केंद्र:**
 - शहर नरितर वसितार करने वाले शक्तिके केंद्र होते हैं, जो कस्बों और गाँवों की कीमत पर अपनी स्थिति को सुदृढ करते हैं।

शहरी रोज़गार योजनाओं का महत्त्व:

- ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मज़बूत करके सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करता है।
- यह शहरी नविसियों को काम करने का वैधानिक अधिकार देता है और इस तरह संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित करता है।
 - उदाहरण- मध्य प्रदेश में नई राज्य सरकार ने "युवा स्वाभिमन योजना" शुरू की है
- यह शहरी युवाओं के बीच कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिये रोज़गार प्रदान करता है और बेरोज़गारी की चिंताओं को दूर करता है।
- इस तरह के कार्यक्रम कस्बों में बहुत ज़रूरी सार्वजनिक नविश ला सकते हैं, जो बदले में स्थानीय मांग को बढ़ावा दे सकते हैं, शहरी बुनियादी ढाँचे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, अरबन कॉमन्स को बहाल कर सकते हैं, शहरी युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं तथा यूएलबी की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।

सरकार द्वारा की गई अन्य पहलें:

- **समाइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन**
- **पीएम-दकष योजना**
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)**
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)**
- **स्टार्ट अप इंडिया योजना**
- **झारखंड:**
 - बरिसा हरति ग्राम योजना (BHGY), नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना (NPJSY) और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना (VSPHKVS)।

आगे की राह:

- शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - आजीविका सुरक्षा जाल का व्यापक कवरेज होना चाहिये। **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)** द्वारा प्रदान किया गया ऐसा जाल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है।
- मौजूदा वित्तीय क्षेत्र में शहरी आजीविका योजना शुरू की जा सकती है।
 - संघ और राज्य मलिकर संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं तथा शहरी स्थानीय नकियों को सशक्त बना सकते हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित किये जाने से शहरी क्षेत्रों में पलायन नहीं होगा क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने की उच्च लागत का ऑफसेट प्रभाव पड़ता है।
- परसिंपत्त निर्माण से सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इसे परसिंपत्त निर्माण या मज़दूरी-सामग्री अनुपात तक सीमित करना शहरी

परस्थितिमें [उपानुकूलतम](#) (Suboptimal) हो सकता है ।
◦ नगरपालिका सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indira-gandhi-shahri-rozgar-guarantee-yojana>

